UGC APPROVED JOURNAL - 47746
© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

नक्सली प्रभाव व समाजिक समूह व आतंकवाद का तुलनात्मक विमर्श

[1]**Manoj Singh Yadav,** Research Scholar
[2]**Dr. Hemlata Mishra,** Professor
Department Of Political science, Shri Dev Suman University
Rishikesh campus Haridwar

संदर्भ

भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी। नक्सलबाड़ी गाँव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किये जा रहे के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इन नेताओं में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी का नाम प्रमुख है। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था (इसीलिये इसे माओवाद भी कहा जाता है) और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। भारत में जहाँ वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित था वहीं आज का माओवाद चीन से प्रभावित है। ये मौजूदा माओवाद हिंसा और ताकत के बल पर समानांतर सरकार बनाने का पक्षधर है। इसके अलावा अपने उद्देश्य के लिये ये किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित मानते हैं।

प्रस्तावना

नक्सलवाद साम्यवादी क्रान्तिकारियों के उस आन्दोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई है जहाँ भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 मे सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आन्दोलन का आरम्भ किया । मजूमदार चीन के कम्यूनिस्ट नेता माओत्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से थे और उनका मानना था कि भारतीय श्रमिकों एवं किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ उत्तरदायी हैं जिसके कारण उच्च वर्गों का शासन तन्त्र और फलस्वरुप कृषितन्त्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया है। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रान्ति से ही समाप्त किया जा सकता है। 1967 में ष्नक्सलवादियोंष ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक रूप से स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के विरुद्ध भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। 1971 के आंतरिक विद्रोह (जिसके अगुआ सत्यनारायण सिंह थे) और मजूमदार की मृत्यु के बाद यह आंदोलन एकाधिक शाखाओं में विभक्त होकर कदाचित अपने लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया। फरवरी 2019 तक, 11 राज्यों के 90 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। आज कई नक्सली संगठन वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक पार्टी बन गये हैं और संसदीय चुनावों में भाग भी लेते है। परन्तु बहुत से संगठन अब भी छद्म लड़ाई में लगे हुए हैं। नक्सलवाद के विचारधारात्मक विचलन की सबसे बड़ी मार आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को झेलनी पड़ रही है।

नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गाँव से हुई थी। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता चारु माजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरु किया। माजूमदार चीन के कम्यूनिस्ट नेता माओत्से तुंग के बड़े प्रशसंक थे। इसी कारण नक्सलवाद को श्माओवादश भी कहा जाता है। 1968 में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्ससिज्म एंड लेननिज्म (ब्ब्डस्) का गठन किया गया जिनके मुखिया दीपेन्द्र भट्टाचार्य थे। यह लोग मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर काम करने लगे, क्योंकि वे उन्हीं से ही प्रभावित थे। वर्ष 1969 में पहली बार चारु माजूमदार और कानू सान्याल ने भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई शुरू कर दी। भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में सबसे पहले आवाज नक्सलवाड़ी से ही उठी थी। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि 'जमीन उसी को जो उस पर खेती करें'। नक्सलवाड़ी से शुरु हुआ इस आंदोलन का प्रभाव पहली बार तब देखा गया जब पश्चिम बंगाल से कॉंग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस आंदोलन का ही प्रभाव था कि 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल में कम्यूनिस्ट पार्टी सरकार के रूप में आयी और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। सामाजिक जागृति के लिए आरंभित इस आंदोलन पर कुछ वर्षो पश्चात राजनीति का वर्चस्व बढ़ने लगा और आंदोलन शीघ्र ही अपने मुद्दों और मार्गो से भटक गया। जब यह आंदोलन फैलता हुआ बिहार पहुँचा तब यह अपने मुद्दों से पूर्णतः भटक चुका था। अब यह लड़ाई भूमि की लड़ाई न रहकर जातीय वर्ग की लड़ाई बन चुकी थी। यहां से प्रारम्भ होता है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच का उग्र संघर्ष जिससे नक्सल आन्दोलन ने देश में नया रूप धारण किया। श्रीराम सेना जो माओवादियों की सबसे बड़ी सेना थी, उसने उच्च वर्ग के विरुद्ध सबसे पहले हिंसक प्रदर्शन करना प्रारम्भ किया।

मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर आधारित नक्सलवाद की शुरूआत पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में 25 मई 1967 को हुई थी।1 नक्सलवाद के नाम से पुकारा गया। इस आंदोलन को प्रारंभिक नेतृत्व मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी के सदस्य कानू सान्याल, चारू मजुमदार तथा जंगल संथाल ने प्रदान किया। इसके नेतृत्व में नक्सलबाड़ी गांव के बेरोजगार युवको तथा भूमिहीन किसानो ने गांव के भू–स्वामियों, पूंजीपतियों आदि अभिजात वर्ग के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष अभियान चलाया। प्रारंभ में इसका उददेश्य आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सामंजस्य एवं समानता स्थापित करना जिसमें मजदूरो, कृषकों तथा अन्य शोषित वर्ग का प्रभुत्व हो। नक्सलवाद उग्रविचार धारा की पृष्टभूमि पर आधारित लेकिन अलगाववाद से अलग है। नक्सलवाद के चिंतन का मूल आधार चीनी कम्युनिष्ट नेता माओत्सेतुंग का वह कथन जिसमें उसने कहा था कि कांति बंदूक की नॉल से निकलती है। इसी कथन से वशीभूत होकर शोषित लोगो ने हथियार उठा लिये और शक्ति के द्वारा वे सामाजिक बदलाव लाने की जुगत में लग गये।नक्सलवादियों के शिल्पकारों में प्रारंभ से ही वैचारिक मतभेद रहे है। इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर खड़ा करने और किसानो के बीच जीवन व्यतीत करने वाले कानूसान्याल का नाम हमेशा मजुमदार के बाद ही आया। यहां तक कि अकेले अपने दम पर कानूसान्याल जिस नक्सबाड़ी आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उस आंदोलन की विचारधारा भी अपने कामरेड साथी से बिलकूल भिन्न और उलट थी। आपस में संघर्ष कर रहे सीपीआई (एम) के इन दो विद्रोही के बीच गहन वैचारिक मतभेद थे। मजुमदार वर्ग शत्रु को खत्म करने के नाम पर व्यक्तियों को मारने पर जोर देते थे। जबकि सान्याल का जोर इस बात पर था कि किसानो के लिए जमीनों पर दावा किया जाये। मजुमदार का विश्वास था कि सशस्त्र कांतिकारियों का एक छोटा

सा समूह भी कांति कर सकता है, जबकि सान्याल समूचे कामगार वर्ग और खासतौर में किसनों को कांति में शामिल करना चाहते थे। मजुमदार व्यक्तिवादी थे, जबकि सान्याल जन नेता थे। मजुमदार ने बंदूक उठाई और चुनाव समेत सभी लोकतांत्रिक माध्यमों का विरोध किया जबकि सान्याल चुनाव के विरोधी नही थे । सिर्फ उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी कोई रूची नही थी जो गरीबों को उनके बुनियादी अधिकार देने में असफल हो गई थी। इन नक्सलवादी कर्णधारों की लड़ाई कांति की चिंगारी आज अपने विकराल विध्वंशकारी रूपों में सर्वत्र फैलते जा रहे है और इससे लोकतांत्रिक शक्ति को काफी नुकसान हो रहा है। प्रारंभ में इसका मकसद जो भी रहा हों, पर वर्तमान स्वरूप काफी विकृत है। आज नक्सलवाद का तात्पर्य सिर्फ मौत के भयानक रूप से है। जिसकी न कोई शक्ल सूरत है और न ही कोई सीरत। यही वजह हो सकता है कि नक्सली अपनी शक्ल को नकाब से ढक लेते है इसे सिर्फ मौत का पर्याय माना जा सकता है ठीक वैसा ही आतंकवाद का तात्पर्य अतिवाद से है जो अब आतंक का पर्याय बन गया है। आज देश के बारह राज्यों में यह प्रभावी है। महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश , कर्नाटक ,मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर, असम आदि। यहां तक कि अब हरियाणा में भी इसके पांव पसर रहे है।

नक्सलवाद दमनकारी नीतियों मनुवादी सोच और नया हिंसा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ क्रांतिकारी आंदोलन का रूप है जो समय के साथ–साथ विक्रांता से फैलता गया और अपने विशिष्ट भयावह रूप से लोगों को डराता रहा। यह भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के बाद से उत्पन्न हुआ था। गरीबों के ऊपर जुल्म अन्याय और अत्याचार लंबे समय से चलती आ रही है। इस दमन से गरीब वर्गों में हताशा और शासन से निराशा ही इसका मुख्य कारण है। जमींदारों द्वारा गरीब लोगों की खेत पर अपना अधिकार जमा कर उसे हथिया लिया जाता था। शासन–प्रशासन पूंजीपतियों के इशारे पर काम करते थे। अपनी ही जमीन पर मजदूर के रूप में काम करने को बेबस था। इन्हें ढंग सेखाना पहनावा भी नहीं मिल पाता था। इन के मजबूरी का फायदा उठाकर इनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। इन के बहन बेटियों के साथ रखैल की तरह सलूक किया जाता था। इस सबसे इनके मन के भय ने गुस्सा और सरकार के खिलाफ बगावत का रूप ले लिया। गरीब मजदूर वर्ग ने अपनी इज्जत और अस्मिता बचाने के लिए हथियार उठा लिए। फिर यहीं से नक्सलवाद का जन्म हुआ। असल में नक्सलवाद समाज में फैली बुराई ऊंच–नीच छुआछूत दमन जैसी घटनाओं का देन है। गरीब आदिवासी समाज को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती थी जिससे इनकी दैनिक जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी और सरकार इन पर ध्यान नहीं देती थी। इससे इस समुदाय को लगने लगा कि अब शस्त्र उठाना जरूरी है अन्यथा हम अपनी पहचान और अस्मिता को खो बैठेंगे। इन लोगों के मन में धरना बैठ गई कि हथियार के दम पर हम अपना वर्चस्व कायम करेंगे तथा सब में हमारा डर रहेगा और सरकार मेरी हर बात मानेगी।

देशवाशियों का अपने देश के प्रति है जिसमें जन जाति वर्ग के लोगों द्वारा अपने उन अधिकारों व कर्तव्यों की मांग की जाती रही है जिसको कि सरकार द्वारा 1986 वन सरंक्षण अधिनियम के तहत जगंल में रहने वाली मूल जातियों को जगंल व जमीन से बेदखल कर दिया उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया परन्तु सरकार द्वारा ठीक प्रकार से विस्थापित नहीं किया गया, नही उनके रोजी रोटी का उचित प्रबन्ध ही किया गया ऐसे में इस लोगों के सम्मुख दो वक्त के भोजन तक की समस्या आ गयी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित आवाश, बिजली पानी आदि

विभिन्न प्रकार समस्याओं की मांग एक अरसे से किया जा रहा है जो कि प्रारम्भ में संवैधानिक दायरे में रहकर इन लोगों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की लेकिन एक सीमा के बाद जब सरकार उनकी मूलभूत समस्या निराकरण पूर्णतः करने में अक्षम रही तो इन लोगों ने हिंसात्मक तरीका अपना लिया और धीरे–धीरे यही आवाज नक्सलवाद के रूप में देश की आन्तरिक समस्या बन गयी है।

जबकि आतंकवाद 1980 के बाद उभर कर सामने आया इनकी कार्य प्रणाली प्रारम्भ से ही हिंसात्मक रही इनका उद्देश्य सदैव अलगाव वादी रहा। इस विरोध में देश के बाहर से हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयाश किया जा रहा हैं। जिन क्षेत्रों में आतंकवाद जारी है उसे धर्म की सुरक्षा से जोड़कर एक विशेष जाति व धर्म के लोगों में अपने ही देश के प्रति विद्रोह की भावना भरी जाती है जिससे वे अपने ही देश के प्रति बगावत पर उतर आते है।

वर्तमान में भारत की नक्सलवादी समस्या हो या जो विद्रोह हो या गोरखालैण्ड के समर्थक तथा असम में वोडोलैण्ड उल्फा आदि विभिन्न सगंठन इस तरह के आतंकवाद का प्रयोग कर रहे है। उन्हें अपने उदेदश्यों की प्राप्ति हेतु किसी प्रकार की हिंसात्मक दमन कारी विद्रोही गतिविधियो से गुरेज नहीं । नार्को आतंकवाद आंतकवाद का चौथा प्रकार है,जो रूपयों के लिए मादक पदार्थो के धंधों को समर्थन देता है।" क्योकि मादक पदार्थों की तश्करी कर आतंकवादी किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था जो विकास की रीड़ होती है, को प्रभावित करते है। मादक पदार्थ किसी भी राष्ट्र को खोखला कर सकता है। क्योंकि इसका प्रभाव आर्थिक व्यवस्था के साथ ही देश के नागरिक विशेष तौर से युवा वर्ग को अपनी चपेट में ले लेता है। जिससे युवा वर्ग इस नशे का आदि हो कर दिग्भ्रमित हो सकता है, और अपनी मादक तृष्णा को पूरा करने हेतु अपने परिवार समाज यहाँ तक कि अपने देश से भी गद्दारी कर सकता है। आतंकवादियों 13 से 18 वर्ष के मासूम बच्चों को मादक पदार्था के माध्यम से शिकार बना रहे है जो इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर श्मानव बमश तैयार कर रहे है। तालिबान इसका प्रत्यक्ष व सामाजिक उदाहरण है। जहाँ बहुत कम उम्र से ही बच्चों को हिंसात्मक गतिविधियों के लिए आतंकवाद की नर्सरी तैयार की जा रही है

नक्सली समस्या का स्वरूप और समाधान के राज्य विकल्प

अन्याय, गैर बराबरी एवं शोषण के गर्भ से जन्मा नक्सलवाद आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल के दर्शन से प्रभावित होकर भूमिहीन किसान एवं उपेक्षित सामाजिक वर्ग के लोगों द्वारा 1967 में आरंभ किया गया नक्सलवादी आंदोलन की चपेट में देश के अधिकांश हिस्सों में शीघ्र ही यह आंदोलन अपना पाँव पसारने में कामयाब हो गया। नक्सलवाद के उदय के प्रमुख कारणों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक असहिष्णुता को शामिल किया जाता है। सामाजिक व आर्थिक रूप से शोषित एक बड़ा वर्ग नक्सलवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अपनी मुक्ति की राह ढूँढ़ने के लिए नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त हो गया। चीनी कम्यूनिष्ट नेता माओ के दर्शन से प्रभावित होकर चारू मजूमदार ने जिस आंदोलन को आरंभ किया आज वही नक्सलवादी आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जब तक शोषित, पीड़ित, भूमिहीन किसान एवं मजदूर, विस्थापित आदिवासी एवं सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता है, तब तक नक्सलवादी समस्या का स्थायी समाधान संभव

नहीं है। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों स्तरों पर इस समस्या का समाधान दूँढ़ना है। नक्सलवादी आंदोलन जिन परिस्थितियों में पनपा उसमें काफी बदलाव अवश्य आये हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद देश के लिए एक गंभी चुनौती है। समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर वर्षों से प्रयास जारी है। अनेक नीतियाँ बनाई गईं किन्तु उन नीतियों का कार्यान्वय नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है, जो वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसका प्रमुख आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की वर्ग–संघर्ष की अवधारणा है। इस अवधारणा के तहत शोषित एवं उपेक्षित वर्ग अपनी शक्ति संघर्ष से पूंजीपतियों, जमीदारों, साहुकारों और शासकों को अपना शिकार बनाते हैं। अतरू इनकी मुख्य धारणा सर्वहारा शासनतंत्र की स्थापना करना है। नक्सलवाद साम्यवादी विचारघारा पर आघारिक एक हिंसक आन्दोलन है। नक्सलवादी साम्यवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य एवं अधिकार मानते हैं। नक्सलवादियों के दस अधिकार को प्राप्त करने में जो बाधा पहुंचाते हैं, उसे समाप्त कर देना चाहिए तभी सर्वहारा तंत्र की स्थापना हो सकेगी, ऐसी उनकी धारणा है। यद्यपि इनका वास्तविक उददेश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है। लेकिन अकारण हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद अपनाने के कारण यह हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक सामयिक सुरक्षा के रूप में उमरा है। सरकारें अभी तक नक्सल समस्या की प्रकृति भी निर्धारित नहीं कर पा रही हैं

साहित्य पुनरवलोकन

(सिन्धु, 2010) में नक्सलवाद समाधान– मीडिया अध्ययन के निष्कर्ष का अध्ययन किया और पाया कि नक्सलवाद या माओवाद के नाम पर क्रांति कर शोषण मुक्त समाज तैयार करने के लिए इस विचार को लेकर काम साठ के दशक से देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू हो गया था। नक्सलवादी आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ ओडिशा की सीमा पर स्थित बस्तर एवं विशेषकर दक्षिणी बस्तर है। यहां पर स्थित बिजेपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर आदि ऐसे जिले हैं जहां दिन में प्रशासन का कुछ प्रभाव रहता है, वहीं रात को पूरे का पूरा इलाका माओवादियों के कब्जे में चला जाता है। ऐसे ही माओवाद से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण बस्तर के जिले के जनजातीय लोगों ने माओवाद को वैचारिक रूप से चुनौती दी थी। सलवा जुडूम के नाम से बस्तर के लोग इकट्ठा हुए और नक्सलवाद के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ी। सलवा जुडूम आंदोलन ने ही माओवाद को वैचारिक रूप से चुनौती दी। माओवाद के समस्या के समाधान की दिशा में उसने राह दिखाईद्य इस आंदोलन के राजनीतिक, वैचारिक व अन्य पहलुओं पर ओडिशा से प्रकाशित होने वाले हिन्दी व ओड़िया अखबारों ने विभिन्न समय पर संपादकीय, लेख व संपादक के नाम पत्र प्रकाशित हुए । राष्ट्रदीप अखबार में इसको लेकर डा. कुलदीप अग्निहोत्री का एक लेख "सलवा जुडुम माओवादियों के असली चेहरों को नंगा करता है" शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस लेख में डा. अग्निहोत्री ने नक्सलवाद के जन्म से लेकर अब तक के माओवाद की यात्रा तथा वर्तमान के माओवाद को लेकर नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत करने वाले कानू सान्याल के विचारों के जरिये विश्लेषण किया था।

(शर्मागौरव, द.क.) ने समाधान एवं निवारण के उपाय का अध्ययन किया और कहा कि भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो चुका है कि. वह नक्सलवाद की समस्या पर काबू पाने के लिए अधिक गंभीरता से विचार करें। नक्सलवादी प्रत्येक समस्या का समाधान सशस्त्र विद्रोह के जरिए करना चाहते है। इस हिंसात्मक आन्दोलन के

संदर्भ में खतरनाक यह है कि इसने ग्रामीण और दूर–दराज के इलाकों में अच्छा–खासा समर्थन प्राप्त कर रखा है। नक्सलवादी संगठनों की शक्ति बढ़ते चले जाना चिंता का विषय है। यदि नक्सलवादी संगठनों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया तो नक्सलवाद एक जटिल। समस्या के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। वैसे भी यह बात प्रदर्शित हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के अनेक जिलों में नक्सलवादी संगठनों तथा नक्सलियों को अच्छा खासा जन समर्थन तथा सहायता मिल रही है। नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि आखिर अतिवादी वामपंथी आंदोलन से जुड़ी यह विचारधारा अपनी जड़े क्यो जमाती चली जा रही है? क्या कारण है कि गरीब, मजदूर, अशिक्षित जनता का एक वर्ग नक्सलवादियों को अपना समर्थन प्रदान कर रहा है और नक्सलवादियों को अपने उद्धारक के रूप में देख रहा है? कही ऐसा तो नहीं कि सरकार उस वर्ग की समस्याओं का समाधान करने में असफल रही है? नक्सलवाद की समस्या केवल कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी नहीं है।

(Redhu, 2012) में नक्सलवाद का अध्ययन किया और पाया कि नक्सल" शब्द की उत्पत्ति पं. बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई तथा बंगाली भाषा में किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति हेतु बारी शब्द का उपयोग किया जाता है। नक्सलवाद कम्यूनिस्ट क्रांतिकारियों के उस अनौपचारिक आंदोलन का नाम है, जो भारतीय कम्यूनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। भारतीय कम्यूनिस्ट पाटी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरूवात की थी। चारू मजूमदार चीन के कम्यूनिस्ट नेता माओत्सेतुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक थे। माओ के विचारों के अनुसार "क्रांति बंदूक की नली से जन्म लेती है"। नक्सली नेता राज्य सत्ता को हथियाकर चीन के नमूने पर एक दलीय शासन पद्धति कायम करना चाहते थे जैसा कि कुछ समय बाद चारू मजूमदार ने उद्घाटित किया। नक्सलवादी आंदोलन को भी विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते रहे हैं। तीन दशक पूर्व अन्यायपूर्ण भूस्वामित्व तथा शोषणकारी व्यवस्था के प्रत्यूत्तर में आया यह जन आंदोलन सीधे सत्ता के विरूद्ध हो गया है। नक्सली अराजकता का पर्याय बनकर माफिया गिरोहों की तरह कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भय के सहारे धन उगाही करना एवं वर्चस्व स्थापित करना हो गया है। 1990 में नक्सल गतिविधियों में व्यापक मजबूती। उन्होंने अपने संबंधों को नेपाल के माओवादियों के साथ पुख्ता किया, ततूपश्चात पेरू फिलीपाइन्स, श्रीलंका, बांग्लादेश के उग्रवादी संगठनों से अपने गणजोड़ स्थापित किए। माओवादियों के हथियार खरीदने के स्पष्ट प्रमाण मिल चुके हैं। विभिन्न नामों से सक्रिय माओवादियों ने देश के भीतर एक बड़ा नेटवर्क फैला रखा है।

निष्कर्ष :–

नक्सलियों की मनोवैज्ञानिक कार्यवाही का प्रभाव क्षेत्र विशेष तक बाधित नहीं है, अपितु व्यापक स्तर पर, दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है वे अपने विरूद्ध चलने वाली किसी भी मुहिम को उक्त कार्यवाही द्वारा रोकने/अवरूद्ध करने की क्षमता रखते हैं। नक्सली विचारधारा को समूल नष्ट करना होगा। नक्सली गुरिल्ला कार्यवाही जितनी अधिक निपुणता से करते हैं। उनके कहीं अधिक निपुणता से सुरक्षा बलों को प्रतिगुरिल्ला कार्यवाही को अंजाम देना होगा। किसी भी कार्यवाही की क्रियान्वयन में पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आम जनता

के प्रति आत्मीय व्यवहार द्वारा विकास की पर्याप्त संभावनाऐं उत्पन्न कर, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर सुदृढ़ करना होगा अर्थात् उनका मनोबल बढ़ाना होगा।

प्रभावी संप्रेषण नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से न केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बुनियादी और ज्वलंत समस्याओं को जनता के सामने लाया जा सकता है, बल्कि उन समस्याओं को दूर कर वर्षों से अपने मूलभूत अधिकारो और सुविधाओं से वंचित लोगों तक उनका वाजिव हक भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दूर्भाग्य से मौजूदा स्थिति इसके विपरित प्रतीत होता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संप्रेषण में अनेकानेक बाधाएं और समस्याएं है जिसकी वजह से अनेकबार प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश ठीक उसी तरह से प्राप्तकर्ता तक नही पहुंच पाता है,जैसा कि वह अपने मूल स्वरुप में होता है। कई बार तो संदेश का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। प्रभावित क्षेत्र में संप्रेषण,विशेषकर अन्तर सांस्कृतिक संप्रेंषण की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित प्रतीत होता है और इसका व्यापक दूष्परिणाम प्रभावित लोगों के जनजीवन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। शोध के उपरान्त निकले निष्कर्षों से समस्या समाधान की दिशा में बनाई जानेवाली विभिन्न परियोजनाओं में मदद मिलेगी । इसके साथ ही नक्सल प्रभावित ईलाकों के आर्थिक,राजनैतिक और सामाजिक विकास में संप्रेषण की वांछित भूमिका और प्रभावित क्षेत्र की लोगों की अपेक्षाएं भी समाज के सामने आ पायेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सहगल, मेजर जनरल विनोद (2004) "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद" तायल चतुर्वदी (1988) "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय

श्रीवास्तव आर0एस0 "विकासशील समाज में समसामयिक दामगुप्ता, विप्लव (1975), "नक्सलवादी आंदोलनश "मैकमिलन

राम, विमल प्रसाद "पुलिस और समाज", प्रकाशन सदन, होम, इंदौर, नई दिल्ली चतुर्वेदी, शैलेंद्र कुमार "भारतीय पुलिस का इतिहास" (अतीत गौरव पब्लिशर्स, जयपुर, काल से मुगल काल तक) प्रकाशन विभाग सिविल लाइंस, शुक्ल,डा.कृष्णानंद, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां,राधा पब्लिकेशन्स,4231 अंसारी रोड,दरियागंज,नई दिल्ली–110002,फोन––23247003,23254306.

राजकिशोर,माओवाद,हिंसा और आदिवासी,वाणी प्रकाशन,4695 24 ए,दरियागंज,नई दिल्ली–4110002.

सरौलिया, शंकर भारतीय पुलिस–संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य" गौरव त्रिपाठी, शंभूरत्न "भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कतिष

भूषण पी.एस., (1998) श्पुलिस और समाजश मनीषा पब्लिकेशन, नवल, चंदनमल, (1992) भारतीय और पुलिसश राजस्थानी

भटनागर, सतीशचंद्र, (1983) श्पुलिस मार्गदर्शिकाश द लायर्स होम, इंदौर, चतुवेदी, मुरलीधर (1982) अपराध–शास्त्र एवं अपराध प्रशासनश, इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशंस, इलाहाबाद,

शर्मा, ब्रजमोहन, (1989) भारतीय पुलिसश, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, यादव, विमलेश, (2002) अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिकाश, सृजक प्रकाशक, गाजियाबाद,

बाबेल, बसंतीलाल, (1988) अपराधशास्त्रश ईस्टर्न बुक कंपनी, पाण्डेय, अजय शंकर, (2000) स्वाधीनता संघर्ष और पुलिसश, प्रभात प्रकाशन दिल्ली द्य राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली,

सकक्ना,विवेक एवं सुशील राजेश,नक्सली आंतकवाद,प्रभात प्रकाशन4 ध्द 11,आसफ अली रोड,नई दिल्ली–110002.

तनेजा, पुष्पलता, (1997) भारतीय प्रजातंत्र और पुलिसश, विधि" पंचशील प्रकाशन नई दिल्ली । सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली,

शाह, गिरिराज, (1998) अपराध, अपराधी और पुलिसश, पुलिस की भूमिका" प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली द्य हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर,

शुक्ल,पंडित,केदारनाथ,बस्तर,भूषण,नवकार,प्रकाशन,बालाजी